संकट तेजी से बढ़ रहा है और लगभग एक तिहाई विकास खण्डों में जल स्तर इतना गिर गया है कि हैंडपंपों तक ने काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भूगर्भ जल के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भूजल स्तर के दीर्घावधिक प्रेक्षण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरदोई, सीतापुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर, खीरी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, और प्रतापगढ़, जिलों के कुछ स्थानों में चार मीटर से अधिक की गिरावट आई है। मई, 1992 और मई, 1993 के बीच सोनभद्र और बांदा जिलों के कुछ स्थानों में भी 4 मीटर से अधिक की मौसमी गिरावट पाई गई है । जब जल स्तर पम्प की अंतर्ग्रहण क्षमता से नीचे चला जाता है तो हैंडपम्प काम करना बन्द कर देता है । ऐसा तब होता है जब पंप को जल स्तर की गिरावट की सभावना के अनुसार अधिक गहराई में नहीं लगाया जाता । केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में भूजल के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए नाजुक ब्लाकों में भूजल के पुनर्भरण की स्कीम बनाई है ।

नर्मदा बांध के संबंध में पुनरीक्षण समिति की स्थापना

808. **श्री राजू भाई ए. परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनुरोध पर विवादित नर्मदा बांध के मामले पर एक पुनरीक्षण समिति स्थापित करने जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ोदा के शीर्षस्थ व्यक्तियों ने सरकार को पुनरीक्षण समिति की स्थापना करने के खिलाफ इस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि इससे गुजरात राज्य क्षेत्र के लोगों के हितों पर असर पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन): (क) मध्य प्रदेश और महराष्ट्र राज्य सरकारों से नर्मदा (सरदार सरोवर) बांध के लिए पुनरीक्षा समिति की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) सरदार सरोवर परियोजना के लिए पुनरीक्षा समिति की स्थापना के विरुद्ध बड़ौदा और गुजरात के अन्य क्षेत्रों के लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं चूंकि संघ सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए ऐसे अभ्यावेदनों के उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए हैं ?

उत्तर प्रदेश में बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं

809. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या जल - संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चल रही बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन परियोजनाओं की स्थिति क्या है और इन्हें कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (घ) सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है (देखिए परिशिष्ट 168, अनुपत्र सं० 14)

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

810. *[Transferred to 4th August* 1993]

Joint venture of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra to float 1450 MW Hydel project

811. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the Government of Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra have agreedto float another company in Joint Sector for completing the work on the 1450 MWHydro-Power Project ;

(b) if so, whether this is a part of the Sardar Sarovar Project;

(c) what is the total investment likely to be made in this project;

(d) the extent to which the floa ting of a company in joint sector is likely to reduce the cost ofthepreject;

(e) whether any concrete proposals have been worked out in this regard; and

(f) if so, the detailst there of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDTI-ONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (f) A proposal has been mooted by the Government of Gujarat for a Joint ventre with the participation of the State Governments of Madhya Pradesh and Maharashtra for completing the work of the power component of Sardar Saovar Project. The details of the proposal, the investment to be made would be known only after the proposal is firmed up in consultation with the Union Ministry of Finance and agreements signed

धुस्सी बांध

812. श्री राम नरेश यादव : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1993 के "जनसत्ता" दिल्ली संस्करण में "धुस्सी बांध में दरार पडने से पंजाब के 50 गांव घिरे, उत्तर भारत पर बारिश का कहर" नामक शीर्षक से प्रकासित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो धुस्सी बांध में दरार पडने की बात को ध्यान में रखते हुए आस-पास के ग्रामीण इलाकों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) :

(क) जी हां ।

(ख) पंजाब सरकार द्वारा धुस्सीं बांध में दरारों को बन्द करने का कार्य तेजी से किया गया है । बाढ प्रभावित लोगों को निकालने के लिए और आपाती बाढ सुरक्षा